आकाशवाणी श्री विजयपुरम

14.03.2026 समय : 1905

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सिलचर से तेईस हजार पांच सौ पचास करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

2. सरकार ने घरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया।

3. अंडमान निकोबार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से आज, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

4. अंडमान निकोबार शतरंज संघ की ओर से पैंतीसवीं नेशनल अंडर–17 शतरंज चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सिलचर से तेईस हजार पांच सौ पचास करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने सिलचर के अंबिकापुर में तीन परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में बाईस हजार आठ सौ चौंसठ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला सिलचर हाई–स्पीड कॉरिडोर, लगभग पांच सौ पैंसठ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाला सिलचर टाउन फ्लाईओवर और एक सौ बाईस करोड़ रुपये की लागत वाला पाथरकंडी कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि असम की बराक घाटी भारत को दक्षिण–पूर्व एशिया से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में उभर रही है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद दशकों तक इस क्षेत्र की उपेक्षा के लिए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अवसंरचना विकास पर बल देते हुए कहा कि सिलचर–शिलांग हाई–स्पीड कॉरिडोर की आधारशिला रखे जाने के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यह परियोजना पूर्वोत्तर में पहला एक्सेस–कंट्रोल्ड हाई–स्पीड एक्सप्रेसवे होगा।

<><><><><><><>

सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया है। रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में तीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर–मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। सुश्री सुजाता ने बताया कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के सुनिश्चित की जा रही है। संयुक्त सचिव ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को ईंधन वितरण के दौरान दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आपूर्ति के अलावा अड़तालीस हजार किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है।

<><><><><><><>

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अग्रिम कर ई–अभियान के अंतर्गत करदाताओं को भेजे गए कुछ ईमेल संदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ करदाताओं को ऐसे ईमेल मिले हैं जिनमें 'महत्वपूर्ण लेन–देन' के गलत विवरण दर्ज थे। ऐसे करदाताओं से पिछले ईमेल को अनदेखा करने का अनुरोध किया गया है। विभाग इस त्रुटि को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने लेन–देन के सटीक विवरण की जांच के लिए आयकर ई–फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और 'कम्प्लायंस पोर्टल' के अंतर्गत 'ई–अभियान' टैब का उपयोग करें।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से आज, जिला न्यायालय भवन, पोर्ट ब्लेयर, ए डी आर केंद्र–'प्रयास' के अलावा मायाबंदर, डिगलीपुर और कैंपबेल बे के उप–मंडल न्यायालय परिसरों में वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के सफल संचालन के लिए श्री विजयपुरम में चार, मायाबंदर में एक और डिगलीपुर में एक बेंच का गठन किया गया था। श्री विजयपुरम में आयोजित लोक अदालत में बत्तीस बैंक रिकवरी मामलों का निपटारा कर मौके पर पन्द्रह लाख तिरपन हजार पांच सौ रूपये की वसूली की गई, जबकि बीएसएनएल के पांच मामलों को तीस हजार पांच सौ रूपये और फौजदारी के चार सौ अट्ठारह मामलों का निपटारा कर दस लाख तेरह हजार सात सौ पचास रूपये का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार कैंपबेल बे में मोटर वाहन अधिनियम के तहत अट्ठारह मामलों का निपटारा कर छियालीस हजार नौ सौ पचास रूपये का जुर्माना वसूला गया। मायाबंदर में बैंक रिकवरी के दो मामलों को चौदह लाख रूपये में सेटल किया गया। इसके अलावा, विभिन्न न्यायालयों में लंबित पैंतालीस मामलों में से चौबीस का निपटारा कर बारह हजार सात सौ रूपये जुर्माना वसूला गया। डिगलीपुर में बैंक रिकवरी के दो मामलों और एक बीएसएनएल मामले का निपटारा किया। साथ ही, चौंतीस फौजदारी मामलों को भी सुलझाया गया।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में नशीले पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध एंटी–नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ मिलकर कल वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अभियान चलाया। अभियान के दौरान पांच किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सूचना मिलते ही एंटी–नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के. बिनोज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने तिरपन वर्षीय जगदीश मंडल के सामान की तलाशी ली और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गांजा को जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा अभियान उप–पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स योगिता शर्मा, की निगरानी में चलाया गया।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार शतरंज संघ ने आज, 35वीं नेशनल अंडर–17 शतरंज चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया। यह ट्रायल डेयरी फार्म स्थित 'शतरंज केंद्र' में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 70 शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन ट्रायल में उनके प्रदर्शन और अंतिम रैंकिंग के आधार पर, बालक और बालिका वर्ग से दो–दो खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी 30 मार्च से गुजरात में आयोजित होने वाली 35वीं नेशनल अंडर–17 शतरंज चैंपियनशिप में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। लड़कियों की श्रेणी में कस्तूरी बाई आर पहले और चार्वी डी दूसरे स्थान पर रही। लड़कों की श्रेणी में रोहन सिंह को पहला और विराट जे.एस. को दूसरा स्थान हासिल हुआ। चयनित खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना सहमति पत्र कल, तक व्हाट्सऐप नंबर पर भेजने को कहा गया है।

<><><><><><><>

मुख्य सचिव के सभी विभागों में मासिक मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश के अनुसार आपदा तैयारियों को मजबूत करने और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए कल जहाजरानी सेवा निदेशालय में भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास निदेशालय के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी की देखरेख में आयोजित की गई। इसमें मुख्य प्रशासनिक भवन, सूचना केंद्र और स्टार्स टिकटिंग काउंटर के सभी कर्मचारियों के साथ–साथ निदेशालय की आपदा प्रबंधन टीम ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में खोज और बचाव के साथ प्राथमिक उपचार का अभ्यास किया गया। इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य भविष्य में कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

<><><><><><><>